



बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में SIR की अंतिम तिथि 19 जनवरी तक बढ़ी

नई दिल्ली - भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की समयसीमा को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 19 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। आयोग ने निर्णय किया है कि इन प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों में दावा और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 19 जनवरी तक रहेगी, ताकि बड़ी संख्या में योग्य मतदाता अपने विवरण की पुष्टि या सुधार कर सकें।

निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची अधिक व्यापक, सटीक और अपडेटेड रहे, ताकि आगामी चुनावों में हर योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल हो। नई समयसीमा के तहत मतदाता Form-6 के माध्यम से नाम जोड़ने या विवरण में सुधार के लिए अधिक समय पा सकेंगे। ECI ने प्रत्येक राज्य/संघ शासित

प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिए हैं कि वे इस विस्तार की व्यापक रूप से जागरूकता फैलाएँ, ताकि मतदाता-जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए मीडिया, बृथ-स्तरीय कर्मियों और ई-प्लेटफॉर्म का उपयोग करने को कहा गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसका लक्ष्य मतदाता सूची में नामों की सत्यापन, त्रुटियों का सुधार और डुप्लीकेट/अप्रसंगिक नामों को हटाना है। समय सीमा बढ़ाने से अब लोग अंतिम मौके पर भी अपनी सदस्यता दर्ज करा पाएंगे और भविष्य के चुनावों में मतदान का अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे।

मतदाता आयोग का यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है, जिससे संभावित मतदाता-वंचित होने की संभावना कम होगी।

अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंट की कार्रवाई जारी, मिनियापोलिस में एक और व्यक्ति को गोली लगी



मिनियापोलिस- अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंटों द्वारा प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बुधवार रात मिनियापोलिस में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। अधिकारियों के मुताबिक यह व्यक्ति वेनेजुएला का नागरिक था और एक लक्षित ट्रैफिक स्टॉप ऑपरेशन के दौरान भागने की कोशिश में संघर्ष के समय गोली ब मूलतः आत्मरक्षा में दागी गई मानी जा रही है।

घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना के दौरान एजेंट पर फावड़ा और बर्तन से हमला करने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद एजेंट ने खुद की रक्षा के लिए गोली चलाई। यह घटना मिनियापोलिस में ICE की कार्रवाई के खिलाफ विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बीच हुई है, जहां कुछ हफ्ते पहले एक महिला की ICE एजेंट द्वारा हत्या के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने सार्वजनिक शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण बने रहने का आग्रह किया है।

क्या पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भारत में वोट डाल सकती हैं? जानें SIR और नागरिकता के नियम



NEWS AGENCY |

नई दिल्ली (विशेष संवाददाता) - सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर क्या भारत में वोट डाल सकती हैं और क्या वे SIR (Special Intensive Revision) के तहत फॉर्म-6 भर सकती हैं? इस विषय पर साफ़ किया गया है कि भारत में मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इसलिए सीमा हैदर, जो पाकिस्तान की नागरिक हैं, फिलहाल भारत में वोट नहीं दे सकती।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन करने के लिए फॉर्म-6 भरा जाता है, लेकिन यह भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए संभव है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, न कि नागरिकता देना। इसलिए बिना भारतीय नागरिकता के किसी भी व्यक्ति को

मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं है।

सीमा हैदर ने भारतीय युवक से शादी की है और उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन जनवरी 2026 तक उनकी नागरिकता मंजूर नहीं हुई है, इसलिए वे वोटर सूची में शामिल नहीं हो सकती और मतदान नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही सुनिश्चित किया गया है। अन्य देशों के नागरिक, चाहे वे भारत में स्थायी रूप से रहते हों, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने या मतदान का अधिकार नहीं मिलता।

इसलिए फिलहाल सीमा हैदर के भारत में वोट डालने की कोई वैधानिक संभावना नहीं है, जब तक कि उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाती।

नागपुर महानगरपालिका चुनाव 2026: 156 प्रभागों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, परिणामों पर सबकी नज़र टिकी

नागपुर (विशेष संवाददाता) - नागपुर महानगरपालिका (NMC) चुनाव 2026 के लिए गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया, जिसमें शहर के 156 प्रभागों में मतदाता सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। नतीजों की घोषणा शुक्रवार को मतगणना के बाद की जाएगी, और पूरा शहर परिणामों की ओर उत्सुकता से देख रहा है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं का उत्साह सुबह से ही देखने को मिला, जबकि प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।

नागपुर के मतदाता इस चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मानते हुए वोट देने पहुंचे। शहर में कुल 24 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर संख्या में शामिल हैं। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार मतदान समाप्ति तक लगभग 51% मतदान रिकॉर्ड हुआ है, जिससे यही संकेत मिलता है कि मतदाता अपेक्षित उत्साह के साथ मतदान प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं।



मतदान के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी सुर्खियों में रहीं। केंद्रीय नेता नितिन गडकरी ने वोट डालते समय कहा कि नागपुर के नागरिकों ने भाजपा को पहले भी समर्थन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने मतदाताओं से मतदान के महत्व को समझते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की।

हालांकि मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, पर कुछ शिकायतें भी सामने आईं।

राज्य भर के कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उपयोग किए गए स्याही मार्क को आसानी से धोया जा सकता है, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे ने चुनाव प्रक्रिया और जनमानस के बीच बहस को हवा दी है। मतदान के बीच एक तकनीकी समस्या भी सामने आई जिसमें वार्ड 30 के एक मतदान केंद्र पर बैलेट यूनिट में खराबी आ गई थी। चुनाव अधिकारियों ने तुरंत तकनीकी टीम को बुलाकर उस यूनिट को बदल दिया ताकि

मतदान बिना किसी बाधा के जारी रह सके। इस तत्परता को प्रशासकीय दक्षता का सकारात्मक उदाहरण बताया जा रहा है।

इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना सहित कई राजनीतिक पार्टियाँ, और स्वतंत्र उम्मीदवार शहर में भविष्य की दिशा तय करने के लिए मैदान में हैं। कई स्थानों पर कड़ी राजनीतिक टक्कर दिखाई दे रही है, जिससे स्थानीय विकास और नागरिक सेवाओं के मुद्दों पर मतदाता की प्राथमिकता भी झलक रही है।

प्रचार थमते ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई थी और मतदान दिवस को "मतदाता उत्सव" के रूप में देखा गया। कई प्रभागों में अनुभवी और नई राजनीति की टक्कर ने इस चुनाव को और अधिक रोचक बनाया है। अब सभी की निगाहें शुक्रवार के परिणामों पर टिकी हैं, जब मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों का फैसला साफ हो जाएगा।

मतदान के बीच विवाद: संजय राउत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप



मुंबई (विशेष संवाददाता) - महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के दौरान एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें शिवसेना (UBT) नेता और सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया है कि चुनाव के बीच मतदान केंद्र पर चक्काण ने छाती पर 'कमल' का चुनाव चिन्ह लगाए हुए वोट डाला, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।

राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा कि क्या चुनाव आयोग "सो रहा है" या "बिक गया है", जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का कदम उठाया। उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राउत ने कहा कि ऐसे व्यवहार से मतदाताओं की सोच पर गलत संदेश जाता है और यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।

रवींद्र चव्हाण ने गुरुवार सुबह डॉबिवेली के मतदान केंद्र पर परिवार सहित वोट डाला

था। तस्वीरों और वीडियो में चक्काण को बीजेपी का 'कमल' चिन्ह अपने सीने पर पिन किया हुआ दिखाया गया, जिसे राउत ने सीधा चुनाव आचारण के नियमों का उल्लंघन बताया है। राउत ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्क्रिय रहता है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरा हो सकता है।

इस विवाद ने चुनाव के साथ जुड़ी राजनीतिक लड़ाई को और अधिक गरमा दिया है। विपक्षी दल लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा चुनाव नियमों का सही पालन नहीं कर रही और सत्ता के नजदीक होने के नाते स्वयं को आगे रख रही है। राउत के आरोपों के बाद भाजपा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला मतदाता मनोवृत्ति और चुनाव कनिष्ठता की भावना पर असर डाल सकता है, खासकर तब जब चुनाव आयोग के निर्णयों और नियंत्रण पर बहस चल रही है। अगर चुनाव आयोग इस पर में उचित कार्रवाई नहीं करता है, तो यह चुनाव प्रक्रिया में विश्वास को प्रभावित कर सकता है। यह विवाद नगर निकाय चुनावों के दौरान सामने आया है और इससे राजनीतिक दलों के बीच तनाव और बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है, जिससे चुनाव के निष्पक्ष और निष्कर्षात्मक परिणाम को सुनिश्चित किया जा सके।

BMC ELECTION | **बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स को झटका, BJP-शिंदे सेना को प्रचंड बहुमत, देखें एग्जिट पोल के नतीजे**

BMC Exit Poll 2026: मराठी मुद्दे पर आए साथ, भूले गिले-शिकवे पर एग्जिट पोल ने दिया झटका, बीजेपी-शिंदे के आगे नहीं चली ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी



एग्जिट पोल के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो महायुति को लगभग 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है, जो कि विपक्षी गठबंधनों की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है। इसके विपरीत, ठाकरे-MNS गठबंधन को लगभग 32% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस-संघीय गठबंधन लगभग 13% वोट शेयर के आसपास रह सकता है।

ये एग्जिट पोल नतीजे राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए संकेत हैं कि मुंबई के मतदाता इस बार विकास और प्रशासनिक स्थिरता पर जोर दे रहे हैं, जिससे महायुति के पक्ष में वोट अधिक दिख रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स की मराठी भावना और समन्वय रणनीति इस बार मतदाताओं पर अपेक्षित असर नहीं दिखा पा रही है, जिससे उन्हें राजनीतिक झटका लग सकता है।

मुख्य रूप से यह चुनाव बीएमसी के 227 वार्डों के लिए लड़ा गया है और बहुमत के लिए 114 सीटों का आंकड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक महायुति इस आंकड़े से काफी ऊपर जा रही है, जिससे भाजपा का पहला मेयर भी बीएमसी में बैठने की संभावना दिख रही है।

हालांकि एग्जिट पोल केवल मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से लिए गए रझानों का अनुमान होता है, आधिकारिक परिणाम 16 जनवरी को मतगणना के बाद घोषित होंगे, तभी वास्तविक तस्वीर साफ होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एग्जिट पोल बताई गई रझान जैसी रही, तो यह ठाकरे-गठबंधन के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित होगा और महायुति की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। ये नतीजे बीएमसी चुनाव के भारी सुरक्षा इंतजाम, चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक गठबंधनों पर उठ रहे बहस के बीच आए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुंबई की राजनीति में अगले कुछ सालों के लिए सत्ता संतुलन बदल सकता है।

ओडिशा बौद्ध सर्किट: प्रमुख स्थलों पर आधुनिक शोध योजना



ओडिशा सरकार ने राज्य के प्रमुख बौद्ध धरोहर स्थलों को भारत के बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़ने की रणनीति तैयार की है। उपमुख्यमंत्री प्रभाति परिड़ ने बताया कि रत्नागिरि, ललितगिरि, उदयगिरि, जिरांग और धौली जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए समग्र विकास, हेरिटेज संरक्षण और आधुनिक शोध की पहल शुरू की जा रही है। इसके लिए Light of Buddha Foundation के साथ समझौता किया गया है और एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य इन प्राचीन बौद्ध स्थलों

को राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन सर्किट से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय एवं देशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। इससे न सिर्फ सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

इन स्थलों में रत्नागिरि, ललितगिरि और उदयगिरि को 'डायमंड ट्रायंगल' के नाम से भी जाना जाता है और ये प्राचीन महाविहार तथा बौद्ध कला-संस्कृति के प्रमुख उदाहरण हैं। राज्य सरकार की यह पहल ओडिशा के बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

RJD का बड़ा आरोप: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में घोटाला, हाई कोर्ट से जांच की मांग

बर्फ में बदल गया वासुकि ताल, बर्फ में बदल गया वासुकि ताल,



पटना (विशेष संवाददाता) - राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार और हाई कोर्ट से मामले की गहन न्यायिक जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ और घोटाले सामने आए हैं, जो युवाओं के अधिकार और करदाताओं के धन के साथ धोखा है।

राजनीतिक पटल पर RJD नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन में पंजीकरण, प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट प्रक्रियाओं के दौरान बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और इसके कारण योजना का मूल उद्देश्य — युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार दिलाना — प्रभावित हुआ है।

RJD का दावा है कि सीएजी (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत मिले हैं कि कई बेनिफिशियरी के बैंक खाते, मोबाइल नंबर और ईमेल पते फर्जी पाए गए हैं,

और मूल्यांकनकर्ताओं (Assessors) की जानकारी भी संदिग्ध पाई गई है, जिससे योजना का वास्तविक प्रभाव और पारदर्शिता सवाल के घेरे में है।

इस मामले को लेकर RJD नेताओं ने कहा कि जब योजना में करोड़ों रुपये का निवेश किया गया है, तो इसकी निष्पक्ष और गहन जांच होना आवश्यक है, ताकि पता चल सके कि यही कांग्रेस, RJD या अन्य दलों द्वारा उठाई जाने वाली जांच निगरानी की मांग क्यों महत्वपूर्ण है।

RJD की मांग है कि हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संपूर्ण जांच की निगरानी करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत वितरित धन का कोई भी हिस्सा गलत तरीके से उपयोग नहीं हुआ।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि यह मामला अदालत में जाता है, तो इससे केंद्रीय योजनाओं की निगरानी प्रक्रियाओं, सरकार की जवाबदेही और भ्रष्टाचार रोधी तंत्रों पर विस्तृत बहस शुरू हो सकती है। यह आरोप खासकर तब आया है जब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव को लेकर आम जनता में बढ़ती संवेदनशीलता देखी जा रही है। इस आरोप को लेकर केंद्र सरकार या कौशल विकास विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। मामले की सुनवाई और हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया आने पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।



महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव: जनादेश, शहरी लोकतंत्र और राजनीति की अगली दिशा

संपादकीय...

महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 को 29 नगर निगमों के लिए हुआ मतदान केवल स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं था, बल्कि यह शहरी भारत के लोकतांत्रिक मिज़ाज और राज्य की राजनीति की भावी दिशा का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। देश की सबसे बड़ी और आर्थिक रूप से सबसे सशक्त महानगरपालिका — बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) — के कारण इन चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहीं। लंबे अंतराल के बाद हुए इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी मतदाता अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक क्षमता और भविष्य की दिशा को भी ध्यान में रखकर मतदान कर रहा है।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और शाम तक औसतन लगभग 46 से 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह प्रतिशत भले ही अत्यधिक उत्साहजनक न लगे, लेकिन पिछले नगर निगम चुनावों की तुलना में इसे एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है। विशेष रूप से दोपहर के बाद मतदान में आई तेजी यह दर्शाती है कि शहरी मतदाता अब भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका को गंभीरता से ले रहा है, भले ही शुरुआती घंटों में उदासीनता दिखाई दी हो।

इन चुनावों का केंद्र बिंदु मुंबई रहा। बीएमसी केवल एक नगर निगम नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा शहरी प्रशासनिक तंत्र है, जिसका वार्षिक बजट कई राज्यों के बराबर माना जाता है। ऐसे में बीएमसी पर नियंत्रण राजनीतिक दलों के लिए न केवल प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं की दिशा तय करने का अवसर भी है। शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार हुए इस चुनाव को ठाकरे गुट की राजनीतिक पकड़ और महायुति गठबंधन की शहरी स्वीकार्यता की कसौटी के रूप में देखा जा रहा है।

मतदान समाप्त होते ही सामने आए एग्जिट पोल संकेतों ने यह जरूर बताया है कि महायुति गठबंधन को कई प्रमुख नगर निगमों में बढ़त मिल सकती है, विशेष रूप से मुंबई में। हालांकि, राष्ट्रीय संपादकीय दृष्टि से यह याद रखना आवश्यक है कि एग्जिट पोल अंतिम निर्णय नहीं होते। वे केवल मतदाताओं के तत्काल रुझान को दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक जनादेश का निर्धारण मतगणना के बाद ही होता है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि कई बार एग्जिट पोल और वास्तविक परिणामों के बीच स्पष्ट अंतर देखा गया है।

इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि मतदाता किन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और आवास जैसे मुद्दे हमेशा से केंद्र में रहे हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता जैसे व्यापक प्रश्न भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते दिखे। शहरी मतदाता यह संकेत दे रहा है कि वह केवल वादों से नहीं, बल्कि शासन की क्षमता और क्रियान्वयन से संतुष्ट होना चाहता है।

चुनाव आयोग द्वारा किए गए सुरक्षा और निगरानी प्रबंधों ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत किया। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, ईवीएम की निगरानी और मतदाता पहचान की सख्ती ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। कुछ स्थानों पर सामने आए आरोप-प्रत्यारोपों के बावजूद, समग्र रूप से चुनाव प्रक्रिया पर किसी बड़े व्यवधान की रिपोर्ट नहीं आई, जो लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो महाराष्ट्र के ये नगर निगम चुनाव आने वाले वर्षों की राजनीति के लिए संकेतक की भूमिका निभा सकते हैं। शहरी भारत की राजनीतिक पसंद अक्सर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यदि एग्जिट पोल में दिख रहे रुझान परिणामों में बदलते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि शहरी मतदाता गठबंधन राजनीति और स्थिर शासन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं, यदि परिणाम अपेक्षाओं से भिन्न आते हैं, तो यह विपक्षी दलों के लिए आत्ममंथन और पुनर्गठन का अवसर भी बन सकता है।

इन चुनावों से एक और महत्वपूर्ण संदेश निकलता है — शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्मार्ट सिटी, मेट्रो, डिजिटल सेवाएं और सतत विकास जैसे राष्ट्रीय एजेंडे सीधे नगर निगमों की कार्यक्षमता से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन संस्थाओं का सशक्त और जवाबदेह होना लोकतंत्र की सेहत के लिए अनिवार्य है।

अब जब 16 जनवरी 2026 को मतगणना होनी है, तो पूरे देश की निगाहें अंतिम परिणामों पर होंगी। लेकिन परिणाम चाहे जो हों, यह चुनाव एक बात स्पष्ट करता है — भारतीय लोकतंत्र में शहरी मतदाता अब अधिक जागरूक, अपेक्षाकृत विवेकशील और दीर्घकालिक सोच के साथ मतदान कर रहा है। यही प्रवृत्ति लोकतंत्र को केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि जनभागीदारी की सशक्त प्रक्रिया बनाती है।

अंततः, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव हमें यह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती केवल विधानसभाओं या संसद से नहीं, बल्कि नगर निगमों और स्थानीय निकायों से भी तय होती है। शहरी शासन जितना सक्षम और उत्तरदायी होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। यही इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी और संत नामदेव : भारतीय संत परंपरा में धर्म, मानवता और बलिदान का अद्वितीय संगम

विशेष लेख—

नांदेड में 24 और 25 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रहे हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर भारतीय संत परंपरा के दो महान स्तंभ—श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी और संत नामदेव महाराज—की विचारधारा, त्याग और मानवतावादी दृष्टि का स्मरण स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो उठता है। यद्यपि दोनों महापुरुष अलग-अलग युगों और क्षेत्रों में अवतरित हुए, फिर भी उनके विचार भारतीय आध्यात्मिक चेतना की एक ही अविरल धारा से जुड़े हुए दिखाई देते हैं।

भारतीय संत परंपरा विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है। इसी परंपरा में महाराष्ट्र की धरती से निकले वारकरी संप्रदाय के महान संत नामदेव महाराज और सिख धर्म के नवें गुरु, हिंद-दी-चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ही महापुरुषों ने धर्म, मानवता, समता और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने-अपने मार्ग चुने, किंतु लक्ष्य एक ही रहा —मानव कल्याण।

संत नामदेव महाराज 13वीं-14वीं शताब्दी के महान भक्त संत थे। उन्होंने विठ्ठल भक्ति के माध्यम से समाज में समता, करुणा और नामस्मरण का संदेश दिया। जाति-पाति, ऊँच-नीच जैसे भेदभाव को नकारते हुए उन्होंने आम जनमानस को ईश्वर से सीधे जुड़ने का अधिकार दिया। उनके अभंगों में मानवता, प्रेम, सामाजिक एकता और सर्वधर्म समभाव की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है।



संत नामदेव की ख्याति केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर भारत तक फैली। उनके अनेक अभंग पंजाबी भाषा में समता और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने-अपने मार्ग चुने, किंतु लक्ष्य एक ही रहा —मानव कल्याण।

दूसरी ओर, 17वीं शताब्दी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी ने धर्मस्वातंत्र्य और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तत्कालीन शासकीय अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। धर्म के लिए शीश

कटाया जा सकता है, पर आत्मसम्मान और सत्य से समझौता नहीं—यही उनका जीवन संदेश रहा। इसी कारण उन्हें हिंद-दी-चादर की गौरवपूर्ण उपाधि प्राप्त हुई।

यद्यपि संत नामदेव और श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी के कालखंड में लगभग तीन शताब्दियों का अंतर है, फिर भी उनके विचारों में अद्भुत समानता दिखाई देती है। दोनों ने ईश्वर की एकता, मानव मूल्य, धार्मिक सहिष्णुता और अन्याय के प्रतिकार पर बल दिया। संत नामदेव ने भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ा, जबकि गुरु तेग बहादुर साहिबजी ने त्याग और बलिदान के माध्यम से धर्मरक्षा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया।

भारतीय संत परंपरा की सांस्कृतिक एकात्मता का सबसे सुंदर उदाहरण यह है कि संत नामदेव महाराज के अभंग सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान पाते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं, बल्कि वह समावेशी और सर्वमानविक दृष्टि रखती है।

आज के समय में, जब समाज अनेक प्रकार की धार्मिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी और संत नामदेव महाराज के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सौहार्द, मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेना समय की आवश्यकता है। गुरु तेग बहादुर साहिबजी का बलिदान और संत नामदेव की भक्ति परंपरा भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दीपस्तंभ के समान है।

350वें शहीदी समागम के अवसर पर महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में विविध जनजागरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह आयोजन न केवल स्मरण का, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात कर समाज में उतारने का संकल्प लेने का भी अवसर है।

(विशेष लेख)—
चंद्रकांत कारभारी
उपसंपादक, जिला सूचना कार्यालय, हिंगोली
(स्रोत ज़िला माहिती कार्यालय नांदेड)

ईरान को एक मौका और मिले...

WORLD NEWS | ईरान को एक मौका और मिले...

ईरान को एक मौका और मिले... सऊदी-कतर-ओमान की अमेरिका से अपील, क्या मानेंगे ट्रंप?

NEWS AGENCY

सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए बातचीत की कोशिशें की हैं। इन देशों को डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इससे मध्य पूर्व अस्थिर होगा और सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है।

वॉशिंगटन: सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए मनाने की कोशिश की है। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो जाएगा। उन्हें अभी से क्षेत्र में गंभीर नतीजों का डर सता रहा है। ऐसे में इन तीनों देशों ने अमेरिका से शक्ति बरतने और इंतजार करने की अपील की है। ट्रंप ने ईरान को कई बार हमले की धमकी दी है।



ईरान को मौका देने की गुजारिश

बातचीत अभी भी जारी है।"

एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि खाड़ी के इन तीनों देशों ने "राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझाने के लिए आखिरी समय में एक लंबी, जोरदार, राजनयिक कोशिश की कि वे ईरान को अच्छे इरादे दिखाने का मौका दें।" उन्होंने आगे कहा, "बनाए गए भरोसे और मौजूदा अच्छे माहौल को मज़बूत करने के लिए

ट्रंप पर हमले की तस्वीर शेयर कर ईरान ने दी धमकी

ईरान ने एक तस्वीर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई,

वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा, बेचा 50 करोड़ डॉलर का ऑयल; अमेरिका का भरेगा खाता

वॉशिंगटन - संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के कूड तेल की पहली बिक्री लगभग 500 मिलियन डॉलर की सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जो दोनों देशों के बीच इस महीने हुए लगभग 2 अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते का हिस्सा है। इस सौदे के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की पहल शुरू की है, जिससे वॉशिंगटन के नियंत्रण में इस संपत्ति का व्यापार और राजस्व सृजन सुनिश्चित होगा।

सूत्रों के अनुसार यह राशि अमेरिका-नियंत्रित बैंक खातों में रखी गई है, जिसमें क्रतर स्थित मुख्य खाता भी शामिल है, ताकि वित्तीय लेनदेन कानूनी जटिलताओं से मुक्त होकर सुचारू रूप से हो सके। अतिरिक्त बिक्री के लिए तैयारियाँ जारी हैं और आने वाले दिनों में और सौदे की उम्मीद जताई जा रही है।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस शुरुआती तेल बिक्री से हुई आय यूएस के नियंत्रण वाले बैंक खातों में रखी गई है,



जिनमें प्रमुख कतर में स्थित खाता भी शामिल है। इस खाते को न्यायिक या अन्य दावों से सुरक्षित रखने के लिए एक 'तटस्थ' स्थान के रूप में चुना गया है, ताकि इस धन पर कोई विवाद उत्पन्न न हो सके और यह सुलभ रूप से नियंत्रित रहे। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह ऊर्जा

समझौता ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रणनीतियों गहन रूप से चल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन की योजना यह भी है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में और तेल बिक्री की जाएगी, जिससे वेनेजुएला की तेल संपदा का अंतरराष्ट्रीय बाजार में सक्रिय उपयोग हो सके।

यह सौदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनका मानना है कि वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों का वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने और अमेरिका तथा वेनेजुएला दोनों के हित में उपयोग किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यह कदम न केवल दोनों देशों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि वेनेजुएला की तेल अवसरंचना को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगा।

विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की तेल बिक्री योजनाएँ वैश्विक ऊर्जा बाजार के संतुलन पर भी प्रभाव डाल सकती हैं और इससे तेल की भविष्य की कीमतें, निवेश प्रवाह तथा अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालाँकि, वास्तविक प्रभाव और दीर्घकालिक नतीजे आने वाले समय में स्पष्ट होंगे।



नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



Friday 16th January 2026 वर्ष - 9 , अंक 261 , पृष्ठ 04

नांदेड़ मनपा चुनाव: मतदान शुरू हुआ, लेकिन सुबह मतदाताओं में उत्साह दिखा फीका



नांदेड़ : आज नांदेड़ महानगरपालिका के २० प्रभागों में ८१ सीटों के लिए मतदान का प्रथम चरण सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही चुनावी प्रक्रिया का पहला सत्र चला, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षा से कम रही। सुबह 9:30 बजे तक केवल 7.16% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे सुबह का माहौल शांत और बेरंग दिखा।

कुल ४९१ उम्मीदवारों मैदान में होने के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर मतदाता भीड़ का अभाव रहा और कई बूथों पर शुक-शुकाट

ठाणे महापालिका चुनाव में मतपेटी विवाद: वार्ड 3 में बस रोकी, तनाव बढ़ा



ठाणे (विशेष संवाददाता) - ठाणे महापालिका चुनाव के बाद वार्ड 3 में मतपेटियों को ले जा रही बस को रोककर शिंदे सेना के पदाधिकारियों और समर्थकों ने आधा घंटा रोके रखा, जिससे गंभीर तनाव पैदा हुआ। आरोप था कि बस में अनधिकृत लोगों ने मतपेटियाँ उठाई हैं और सुरक्षित गंतव्य तक नहीं ले जाया जा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और बस को समय के बाद रवाना कराया गया।

घटना मानपाडा इलाके की सेंट जेव्हियर्स स्कूल के निकट घटी, जहां से मतपेटियाँ मतगणना केंद्र तक ले जाई जा रही थीं। इस दौरान शिंदे सेना और अपक्ष उम्मीदवारों के समर्थक आमने-सामने आए, जिससे तनाव का माहौल बन गया। घटना के बाद स्थानीय निवडणूक प्राधिकारी और पुलिस दोनों ने स्थिति नियंत्रण में ली। इस घटना से पहले ठाणे के प्रभाग 1 में भी मतपेटियों का बिना सुरक्षा के घुमाया जाना दर्शाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे विवाद और बढ़ा है। अधिकारी इन मामलों की गहन जांच कर रहे हैं। (

बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल 2026 : महायुती को बहुमत का अनुमान, ठाकरे गुट को कड़ी टक्कर



NEWS AGENCY |

मुंबई - मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-एकनाथ शिंदे शिवसेना (महायुती) को बहुमत के करीब पहुंचते संकेत मिले हैं। यह चुनाव 9 वर्षों के बाद बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर ठाकरे परिवार का प्रभाव बीएमसी में गहरा रहा है।

एग्जिट पोल रिपोर्टों के अनुसार महायुती गठबंधन 114 सीटों के बहुमत लक्ष्य के करीब पहुंच सकता है। साम टीवी के एक्जिट पोल में महायुती को मजबूत स्थिति में बताया गया है और दावा है कि सत्ता के लिए कटि की टक्कर बन रही है।

वहीं, ठाकरे बंधुओं (उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे) और उनके सहयोगी दलों के बीच गठबंधन मजबूत प्रयास कर रहा है, पर एग्जिट पोल संकेत देते हैं कि उन्हें अपेक्षित सीटों की संख्या हासिल नहीं हो सकती। इससे यह चुनाव राजनीतिक प्रतिष्ठा की

सीधी टक्कर बन चुकी है।

इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन में शिवसेना (UBT), MNS (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) और NCP (Sharad Pawar faction) शामिल हैं, जबकि महायुती में भाजपा और शिंदे-समर्थित शिवसेना मुख्य दल हैं। विभिन्न सर्वे में महायुती को सीटों की बढ़त दी जा रही है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि बीएमसी में सत्ता का संतुलन बदल सकता है।

हालांकि, एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान हैं, और वास्तविक परिणाम 16 जनवरी 2026 को मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे, जब प्रत्येक वार्ड में पार्षदों की संख्या तय होगी।

इस चुनाव को मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक ठाकरे-निर्घ्नित चेहरा अब भाजपा-शिंदे गठबंधन की चुनौती का सामना कर रहा है।

नांदेड़ (विशेष संवाददाता) - नांदेड़ नगर निगम चुनाव से महज कुछ घंटे पहले कांग्रेस की महिला उम्मीदवार सारिका भालेराव के पति शिवाजी भालेराव पर एक भयावह हमला हुआ, जिससे चुनावी माहौल में भारी तनाव फैल गया है। यह दर्दनाक घटना वार्ड न.1 के बाहर मंगलवार देर रात उस वक्त घटी, जब शिवाजी भालेराव अपने घर के सामने बैठे थे। अचानक छह नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए और तेज धाटदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह हमला चुनावी हिंसा का हिस्सा हो सकता है।

हमलावरों ने तलवारबाजी करते हुए शिवाजी पर ताबड़तोड़ वार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक कुरसी का उपयोग कर खुद को तुरंत बचाया, जिससे किसी बड़े कटघात से बचाव संभव हो पाया। स्थानीय निवासियों की तत्परता ने भी हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया। घटना के बाद घायल शिवाजी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल

छत्रपती संभाजीनगर चुनाव ड्यूटी लापरवाही: 155 सरकारी कर्मचारियों पर FIR, प्रशासन की कड़ी कार्रवाई



पुलिस शिकायत सिटी चौक थाना में दर्ज कराई गई, जिसमें 56 प्रेसीडिंग अधिकारी, 24 पोलिंग अधिकारी PO1, 50 पोलिंग अधिकारी PO2 और 25 पोलिंग अधिकारी PO3 सहित कुल 155 अधिकारियों का नाम शामिल है, जिन्होंने 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप सामना किया।

प्रशासन के अनुसार इन कर्मियों की गैरहाजिरी से चुनाव व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और मतदान केंद्रों पर ड्यूटी कर्मियों की कमी के कारण प्रशासन को संसाधन पुनर्व्यवस्थित करना पड़ा। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के इस



रहा है और स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

घटना ने नगर निगम चुनाव के संवेदनशील और तनावपूर्ण माहौल को और अधिक भड़का दिया है। वार्ड वासियों में खोफ का माहौल है और कई मतदाता अब चुनावी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नांदेड़ पुलिस ने इस हमले के

दी है, क्योंकि चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति से मतदाता सेवा, मतदान संचालन औरादिकारियों का बोझ बढ़ गया। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः चुनाव ड्यूटी में शामिल कर्मचारी प्रशिक्षण से लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, EVM संचालन और मतदाता सहायता जैसे कार्यों में तैनात रहते हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कानून के उल्लंघन को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसी किसी भी लापरवाही पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए गए कर्मचारियों पर आगे की कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है।

इस घटना से यह संदेश जाता है कि चुनाव ड्यूटी को नजरअंदाज करना अब महज प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि गंभीर विधिक अपराध माना जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम है।

BMC एग्जिट पोल : फडणवीस की भविष्यवाणी पर पुख्ता संकेत, राज-उद्धव गुट को बड़ा झटका



सीटों में अपेक्षित कमी दिखाई गई है।

इन अनुमानों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि महायुति गठबंधन 227 सदस्यीय बीएमसी में बहुमत के आंकड़े 114 से काफी ऊपर जा सकता है, जिससे भाजपा-शिंदे शिवसेना को सत्ता में मजबूत स्थिति मिल सकती है। इससे पहले फडणवीस ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कहा था कि महायुति बीएमसी में निर्णायक जीत हासिल करेगी, और एग्जिट पोल के इन रुझानों को देखकर ऐसा अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उनकी बात सही दिशा में जा रही है।

राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना-UBT की साझेदारी के बावजूद भी एग्जिट पोल इन दलों को अपेक्षित समर्थन नहीं दे रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरणों में बदलाव का संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार एग्जिट पोल केवल अनुमान हैं, और अंतिम निर्णय मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महायुति को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है।

इससे पहले बीएमसी का नियंत्रण लंबे समय तक ठाकरे गुट की पार्टी के पास रहा है, लेकिन इस बार की स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, जिससे मुंबई की राजनीति में सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव संभव है।

पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव: 58% मतदान, 692 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद

पिंपरी-चिंचवड : गुरुवार को पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव में सरासरी 58% मतदान दर्ज हुआ। 32 प्रभागों में 128 स्थाओं में से दो सीटें बिनविरोध चुनी गईं, और शेष 126 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवारों का भाग्य मतदान यंत्र (ईवीएम) में बंद हो गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम तक शांतिपूर्ण रूप से पूरा हुआ, हालांकि ईवीएम मशीनों में तकनीकी गड़बड़ियां और मोबाइल फोन ले जाने पर विवाद भी कुछ मतदान केंद्रों पर देखने को मिले।

मतदाता सूची के अनुसार महापालिका क्षेत्र में लगभग 17.13 लाख मतदाता हैं,

नांदेड़ लोकसभा सांसद रविंद्र चव्हाण ने की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी हिंसा लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला है, और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि भालेराव परिवार को निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

हमले के बाद नांदेड़ में भारी पुलिस तैनाती और चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सभी संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से पहले ही निपटा जा सके। चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की हिंसा से मतदाताओं में भय का माहौल बना है, जिससे मतदान प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय लोगों और नेताओं ने आशा जताई है कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़े पुलिस एक्शन से न केवल हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा बल्कि नांदेड़ के शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।



पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव: 58% मतदान, 692 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद

पिंपरी-चिंचवड : गुरुवार को पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव में सरासरी 58% मतदान दर्ज हुआ। 32 प्रभागों में 128 स्थाओं में से दो सीटें बिनविरोध चुनी गईं, और शेष 126 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवारों का भाग्य मतदान यंत्र (ईवीएम) में बंद हो गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम तक शांतिपूर्ण रूप से पूरा हुआ, हालांकि ईवीएम मशीनों में तकनीकी गड़बड़ियां और मोबाइल फोन ले जाने पर विवाद भी कुछ मतदान केंद्रों पर देखने को मिले।

मतदाता सूची के अनुसार महापालिका क्षेत्र में लगभग 17.13 लाख मतदाता हैं,

जिनमें पुरुष, महिला और अन्य श्रेणियों के मतदाता शामिल हैं। कुल 2,067 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया चलायी गयी, और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, मतदान का प्रतिशत हौले-हौले बढ़ता गया।

सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ जगह ईवीएम खराब होने के कारण मतदान में देरी हुई, लेकिन अधिकारियों ने पर्यायी यंत्र उपलब्ध कराकर मतदान सुचारू रखा। नियमों के तहत मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन की मनाही को लेकर कुछ मतदाताओं ने असंतोष व्यक्त किया, परंतु पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप से शांति बनी रही।

बीएमसी चुनाव 2026: मतगणना आज से, महापौर कौन बनेगा — महायुती या ठाकरे बंधु?

मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 2026 के लिए गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक मतदान संपन्न हो गया और अब आज 16 जनवरी 2026 से मतगणना शुरू हो गई है। 227 प्रभागों के लिए हुए चुनाव में 1,729 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे, और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण ढंग से किया। अब परिणाम के लिए 23 मतगणना केंद्रों पर कार्यवाही जारी है, जिससे अंततः यह स्पष्ट होगा कि मुंबई का महापौर किसके पक्ष में आएगा।

यह चुनाव राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक रूप से शिवसेना का प्रभाव मुंबई महापालिका में रहा है, लेकिन इस बार महायुती (भाजपा-शिंदे शिवसेना) और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। 2017 के पिछले चुनाव में शिवसेना का जोर था, पर अब दोनों ओर से सियासी प्रचार और रणनीति जोरों पर थी।

मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हुई और